

इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स वनिर्माण नीति

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स वनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु [राज्य मंत्रिमंडल](#) ने उत्तर प्रदेश [इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स वनिर्माण नीति-2025 \(UP ECMP-2025\)](#) को स्वीकृति दे दी है।

मुख्य बंदि

- नीति के बारे में:
 - यह नीति **केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वनिर्माण योजना (ECMS)** के अनुरूप है, जिसका नविश लक्ष्य 5,000 करोड़ रुपये है और लाखों रोजगार सृजन का अनुमान है।
- उद्देश्य:
 - नीति का उद्देश्य डिसिप्ले, कैमरा मॉड्यूल और **मल्टीलेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB)** सहित 11 प्रमुख **इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स** के उत्पादन को बढ़ावा देना है।
 - 5,000 करोड़ रुपये के अनुमानित नविश के साथ, इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिससे उत्तर प्रदेश एक प्रमुख नविश गंतव्य बन जाएगा।
- प्रशासनिक ढाँचा:
 - नीति कार्यान्वयन इकाई और एक सशक्त समिति द्वारा समर्थित एक **नोडल एजेंसी स्थापति** की जाएगी, जो नीति के कार्यान्वयन की देखरेख करेगी तथा कुशल शासन एवं पहलों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी।
- समय-सीमा:
 - यह नीति **1 अप्रैल 2025 से पूर्वव्यापी रूप से** प्रभावी होगी तथा इस तथिसे कयि गए नविश नीतितगत लाभों के लयि पात्र होंगे, जो छह वर्षों तक वसितारति होंगे।
- प्रोत्साहन:
 - उद्यमयिों को केंद्रीय **ECMS लाभों के साथ-साथ राज्य सतरीय प्रोत्साहन** भी प्राप्त होंगे, जिससे उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति शृंखला मजबूत होगी और एक आत्मनरिभर पारसिथितिकी तंत्र का नरिमाण होगा।
- महत्त्व:
 - यह नीति इलेक्ट्रॉनिक्स नरिमाण में [नवाचार को प्रोत्साहति](#) करेगी और भारत की **आयात नरिभरता को कम** करेगी, जो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को मजबूत करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है।